



VAN KSHETRIYA VIKAS ME VIKASATMAK KARYKRAMON KA YOGDAN AVM  
PRABHAVON KA ADHAYYAN  
[MANDLA JILE KE VISHESH SANDRABH ME]

वन क्षेत्रीय विकास में विकासात्मक कार्यक्रमों का योगदान एवं प्रभावों का अध्ययन  
(मंडला जिले के विशेष संदर्भ में)

Dr. Tulsiram Jadhav

जमरिया फल्या ग्राम, पोस्ट सोलवन, तहसील वरला, जिला, बड़वानी (म.प्र.) 451666.

## ABSTRACT

राज्य में वनों के व्यापक कटाव को ध्यान में रखते हुए इनकी क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय एवं वन विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है, जिससे राज्य के क्षेत्रीय एवं जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल की पूर्ति के अलावा पर्यावरण संतुलन को बनाया जा सके। क्षेत्रीय एवं जनजातीय समुदायों के जीवन में वनों के कटाव से जो रिक्तता एवं कमी आई उसे पूरा करने की दृष्टि से इन वन क्षेत्रों में क्षेत्रीय व वन विकास की विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू किये गये। वास्तविक जीवन में इन क्षेत्रीय एवं जनजातीय समुदायों में वनों के कटाव से इनकी संस्कृति धीरे-धीरे स्वतः समाप्त होती दिखाई दे रही है। भविष्य में किसी हद तक यदि सामाजिक वाणिज्य, वन विस्तार नीति, पड़त भूमि विकास कार्यक्रम, वाणिज्यिक परियोजना, संयुक्त वन प्रबंधन, वन ग्राम समिति, वन सुरक्षा समिति, ग्राम वन समिति और जी. पी. ए. पी. इत्यादि विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम वनों के संरक्षण के प्रति जन चेतना जागृत करना एवं विकास कार्य में जनसामान्य की भागीदारी स्थापित किया जाना आवश्यक हो जाता है।<sup>1</sup> इस कार्य की सफलता के लिए क्षेत्रीय व जनजातीय समुदायों की सक्रिय सहयोग एवं सद्भावना की आवश्यकता ही नहीं बल्कि अति आवश्यकता है।

## परिचय (INTRODUCTION):

मध्यप्रदेश का गठन सन् 1956 में हुआ था उस समय से लेकर छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद सन् 2009-10 में राज्य का भौगोलिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शासकीय वन भूमि, जनसंख्या एवं पशु संख्या की तुलना करने पर स्पष्ट होता है, कि सन् 1956 में 39 प्रतिशत वन क्षेत्र थे, लेकिन तात्कालिक लाभ के लिए अविवेक पूर्ण ढंग से जंगल उजाड़े गये तथा प्रकृति का दोहन किया गया। जिसके कारण वर्तमान समय में कल 31.71 प्रतिशत वन क्षेत्र शेष रहे हैं। राज्य में वनों के कटाव के कारण निम्नलिखित रहे हैं। कृषि युक्त भूमि को बढ़ावा मिलना, विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके कच्चे माल की पूर्ति, सड़कों का निर्माण एवं राज्य कि विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वनों का ह्रास हुआ है।<sup>2</sup>

राज्य में वनों की कमी के परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न वन विकास कार्यक्रम (योजनाओं वन नीतियाँ एवं अधिनियमों) के माध्यम से वन क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित किया गया है।

## शोध समस्या का चयन (SELECTION OF RESEARCH PROBLEM):

क्षेत्रीय व जनजातीय समुदाय आदिकाल से ही वनों पर निर्भर रहे हैं, किन्तु एक ओर बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि युक्त भूमि को बढ़ावा मिलना, विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके कच्चे माल की पूर्ति, सड़कों का निर्माण एवं राज्य कि विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वनों पर निर्भरता बढ़ने लगी जिसके कारण वनों का कटाव बढ़ने लगे जिससे प्रत्यक्ष रूप से वनोत्पादन व वनों पर निर्भरता घटने लगी एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, वर्षा का कम होना, पर्यावरण दुषित होना जैसे अनेक समस्याओं से क्षेत्रीय व जनजातीय समुदाय सामना करना पड़ रहा है एवं दुसरी ओर उक्त समस्याओं के मध्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय व जनजातीय पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनेक विकासात्मक योजनाओं को लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप लोगों में कौन-कौन से सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? क्या विकासात्मक योजनाओं के कारण इनकी शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रहन-सहन, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है या नहीं? इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए “वन क्षेत्रीय विकास में विकासात्मक कार्यक्रमों का योगदान एवं प्रभावों का अध्ययन” (मंडला जिले के विशेष संदर्भ में) नामक शोध समस्या का चयन किया गया है।

## वर्णन्य उद्देश्य (OBJECTIVE OF STUDY):

- विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन करना।
- विकासात्मक कार्यक्रमों से क्षेत्रीय समसाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

## अध्ययन का महत्व (IMPORTANT OF STUDY):

मध्यप्रदेश के मंडला जिले में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय व अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वनों पर निर्भर है, किन्तु सरकारी योजनाओं के चलते वनोत्पादन जैसे – लकड़ी बैचना, शिकार करना, फल-फूल एकूतित करना आदि कार्य पर रोक लगने से वनों से जुड़े क्षेत्रीय समुदायों की दैनिक जीवनशैली, सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं व्यासायिक जीवन में अनेक समस्याओं एवं परिस्थितियों ने पैर पसारना प्रारंभ कर दिया है। वास्तव क्षेत्रीय व अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग

के स्वतंत्र रूप जीवन यापन की स्वतंत्रता पर अंधकार छाने लगा जिससे क्षेत्रीय व अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ने लगी एवं वही सरकारी योजनाओं के लागू होने से उनकी नितियों के क्रियांवयन, प्रचार प्रसार, भविष्य का आकलन, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का बचाव से संबंधित यह अध्ययन देश के क्षेत्रीय व अनुसूचित जाति, जनजाति लोगों के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा है और उनके विकासार्थ कार्य करने वाली सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं एवं नीति निर्धारकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

## निर्दर्शन प्रक्रिया (SAMPLING PROCESS):

अध्ययन के समग्र (Univers of study) के रूप में मंडला जिले की सभी तहसीले, मंडला, निवास बिछिया व नैनपुर को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक तहसील से 5-5 गांवों का चयन ग्रामों में वनों का क्षेत्रफल तथा वनों पर निर्भर जनसंख्या के आधार पर सोददेश्य प्रतिचयन विधि<sup>3</sup> से चयन किया गया है। इन चयनित कुल गाँवों में से प्रत्येक चयनित गाँव से देव निर्दर्शन विधि द्वारा 20-20 परिवारों को अध्ययन की इकाइयों में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिवार के मुखिया का साक्षात्कार किया गया मुखिया से साक्षात्कार के दौरान विकासात्मक कार्यक्रमों से वनोत्पादनों से उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आये बदलाव वनों से प्राप्त संसाधन का विपणन आदि जानकारीयें एकत्र की गई है।

## समक संकलन के स्रोत (SOURCE OF DATA COLLECTION):

इस अध्ययन हेतु ~~Alfred v k d m s~~ (Primary data) का संकलन का साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, समूह चर्चा आदि के माध्यम से किया गया है तथा द्वितीयक समक (Secondary data) का संकलन विभिन्न मानक पुस्तकों, शोध प्रबंध, संदर्भित पुस्तकों, शोध-पत्रों, जिला गजेटियर पुस्तक, जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, भारतीय जनगणना, विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों (म.प्र. विभाग एवं मंडला वन मंडलों) के प्रतिवेदनों, सरकारी समितियों के प्रतवेदनों आदि के माध्यम से किया गया है।

## अध्ययन के निष्कर्ष (FINDINGS OF STUDY):

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार है—

- वन क्षेत्रीय समुदायों के 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं को वनों से संबंधित चलाये जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी है, जबकि 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को वनों से संबंधित चलाये जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं है। जिसमें से 10 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताये कि पौधा रोपण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, 11 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताये कि वनों में तार फेंसिंग का कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, 36 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताये कि तेन्दू पत्ता नीति चलायी जा रही है, 16 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताये कि वन ग्राम समिति चलायी जा रही है, 8 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताये कि तेन्दू पत्ता नीति एवं तार फेंसिंग कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, 15 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताये कि वन ग्राम समिति एवं तार फेंसिंग कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं एवं 4 प्रतिशत उत्तरदाता ने बताये कि पौधा रोपण एवं तार फेंसिंग कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वन विकास हेतु कई प्रकार के सरकारी कार्यक्रम जैसे – ग्राम वन विकास, वन ग्राम विकास, तेन्दू पत्ता नीति एवं तार फेंसिंग कार्यक्रम व वन्य जाति के विकास के लिए संचालित कार्यक्रम पाये गये

हैं। किन्तु कम समय अवधि के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं।

- अध्ययन क्षेत्र में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये की वनीकरण के बारे कोई जानकारी नहीं है। जबकि 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये की वनीकरण के बारे जानकारी है। जिनमें 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार पाये गये की वनीकरण के माध्यम से जीव संरक्षण, वन संरक्षण के बहत्वपूर्ण है, 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार पाये गये की वनीकरण से हरियाली बनी रहती हैं, 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार पाये गये की वनीकरण से वनों की सुन्दरता बनी रहती है एवं 36 उत्तरदाताओं ने अपने विचार में बताये की वनीकरण से भूमिकटाव को रोकने में सहायता मिलती है।

अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते हुए वनों एवं सरकारी कार्यक्रमों के कारण क्षेत्रीय एवं जनजातीय समुदायों में वनों के बचाव एवं लाभ के महत्व को समझने लगे हैं।

- तत् 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि वन संरक्षण कानून से उनकी जीवन शैली एवं व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं आया है जबकि 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि वन संरक्षण कानून से उनकी जीवनशैली एवं व्यवसाय में अग्रलिखित परिवर्तन आया है। 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि वन्य सामग्री के व्यवसाय में परिवर्तन आया, 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि शहरो में मजदूरी हेतु विस्थापित होना पड़ता है, 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि छोटी-छोटी वन्य सामग्री के कारण दण्ड देना पड़ता है, 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि मजदूरी हेतु दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि समय पर काम नहीं मिलता है, 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि इच्छा के अनुरूप काम नहीं मिलता है एवं 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताये कि काम के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती है।

अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वन संरक्षण के कारण उनकी व्यवसायिक जीवन शैली में अनेक नकारात्मक प्रभाव जैसे – वन्य सामग्री पर प्रतिबंध लगने से बेरोजगारी में वृद्धि, छोटी-छोटी वन्य सामग्री के कारण दण्ड का प्रावधान, समय पर काम नहीं मिलना, मजदूरी हेतु दूसरों पर निर्भर, इच्छा के अनुरूप काम नहीं मिलना एवं काम अनुरूप नहीं मिलना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- वन विकास के सरकारी कार्यक्रम के बारे में उत्तरदाताओं ने अपने सुझाव में 15 प्रतिशत उत्तरदाता फलदार वृक्षों की प्राथमिकता पर बल दिया। 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सागौन व साल वृक्षों की प्राथमिकता पर बल दिया। 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वृक्षों के बड़े होने तक सुरक्षा एवं सिंचाई की आवश्यकता पर बल दिया है। 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ईंधन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए झाड़ीदार वृक्षारोपण पर लगवाने का सुझाव दिये। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वन विकास के कार्यक्रमों में उचित मजदूरी प्रदान करने पर सुझाव दिये तथा 5 प्रतिशत उत्तरदाता वन विकास के कार्यक्रमों का समय – समय पर मूल्यांकन करने पर जोर दिया है।

इस प्रकार इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य में वनों के व्यापक कटाव को ध्यान में रखते हुए इनकी क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय एवं वन विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित जाना चाहिए, जिससे राज्य के क्षेत्रीय एवं जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे माल की पूर्ति के अलावा पर्यावरण संतुलन को बनाया रखा जा सके।

#### उपसंहार (CONCLUSION):

उक्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उत्पादन क्षमता से अधिक विदोहन होने के कारण वनों की दशा बिगड़ती जा रही है। इसलिए वर्तमान में वनों पर निर्भरता कम करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वन भूमि के अतिरिक्त सामुदायिक भूमि, पड़ती भूमि एवं अन्य शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय तथा जनजातीय समुदायों को अपने उपयोग के लिये आवश्यक वृक्षों का उत्पादन कृषि भूमि की मेड़ों पर वृक्ष लगाकर तथा बेकार पड़ी जमीन पर वृक्ष लगाकर करना होगा। वनों पर निर्भरता कम करने के लिये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपाय तथा कम ऊर्जा खपत करने वाले साधनों का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। वनों के संरक्षण के प्रति जनचेतना जाग्रत करना अत्यन्त आवश्यक है एवं विकास कार्य में जनसामान्य की भागीदारी स्थापित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

#### संदर्भ (REFERENCES)

- शील, भद्र, 1999 "वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृ. क्र. 269
- शील भद्र, 1999 "वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृ. क्र. 240-242
- Sharma, S.K. (1990), Universe of Knowledge & Research Methodology, Printwell Publishing House, Jaipur.